दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 14 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 194

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रक ड्रायवरों को मिले 50 लाख रुपए की जीवन बीमा का लाभ

नईदिल्ली (आरएनएस)। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने कोरानावायरस के कहर से पैदा हुए संकट की घड़ी में देशभर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाने में जुटे ट्रक चालकों और उनके सहायकों को मेडिकल स्टाफ, पुलिस व अन्य की तरह बीमा का लाभ देने की मांग की है। एआईएमटीसी ने सरकार से ट्रक चालकों और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के काम में जुटे लोगों को कोरोना महामारी के जोखिम को लेकर 50 लाख रुपए की जीवन बीमा का लाभ देने की मांग की है। साथ हीए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनका मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतारण सिंह अटवाल ने कहा कि कोविड-19 के जोखिम को लेकर ट्रक चालकों और सप्लाई चेन में शामिल लोगों को 50 लाख रुपए की जीवन बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने मौजूदा हालात में ड्राइविंग लाइसेंस और वैध पास के साथ पांच ड्रावइर को एक ट्रक में चलने की इजाजत देने की मांग की जिससे वे अपने वाहन व परिवहन केंद्र तक पहुंच पाए क्योंकि परिवहन व्यवस्था में इस समय ड्राइवर की काफी कमी हो गई है।

चिली में कोरोना से 7213 हुए संक्रमित, 80 की मौत

सेंटियागो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस 'कोविड-19' के कारण चिली में अब तक 80 लोगों की मौत हुई है तथा 7213 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। सरकार की ओर से रविवार को जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान चिली में कोरोना वायरस के 286 नये मामले दर्ज किये गये तथा सात लोगों की मौत हुई। वहीं यहां अब तक 2059 लोग इससे ठीक हुए हैं। चिली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जिन लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है उन्हें एहतियाती तौर पर लॉकडाउन में रहना पड़ेगा।

बवंडर से छह लोगों की मौत

वाशिंगटन । कोरोना वायरस (कोविड 19) से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों का कहर झेल रहे अमेरिका पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी ह। अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में बवंडर आने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई ह। राज्य की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने सोमवार को बताया कि रविवार को बवंडर की चपेट में आने से जेफरसन डेविस काउंटी में तीन, लॉरेंस काउंटी में दो और वाल्टहॉल काउंटी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। ये सभी इलाके राज्य के दक्षिणी हिस्से में हं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह बवंडर 'विनाशकारी' क्षति का कारण बना जिसके चलते राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) को बवंडर आपातकाल जारी करना पडा। यह बवंडर के लिए उच्चतम स्तर की चेतावनी होती ह। एजेंसी ने ट्वीट किया, ये शुरुआती खबरें हं और जानकारी उपलब्ध होने पर अपडेट जारी होते रहेंगे। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रीव्स ने राज्य के लोगों से इन गंभीर तूफानों को बहुत गंभीरता से लेने का आग्रह किया ह। रिपोर्टों के मुताबिक टेक्सास और लुसियाना समेत अन्य दक्षिणी राज्यों में भी बवंडर का प्रकोप देखने को मिला जहां कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयीं। सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक बवंडर के कारण मिसिसिपी और लुसियाना में 60 हजार लोगों को बगर बिजली के रहना पड़ा ह।

देश भर की स्वयंसहायता समूह समय पर कर रही आवश्यक सेवाएं

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है, जिससे बड़ी संख्या में लोग भूख की चपेट में आ गए हैं। इस अभूतपूर्व महामारी और लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, बेघर, गरीब और बहुत से ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं जो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों का पेट भरने के लिए सामुदायिक रसोई एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरी है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसेजरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क की मौजूदगी और स्थानीय स्वायत्त शासन के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें सामुदायिक रसोई/दीदी की रसोई संचालित करने का काम दिलाने में मदद की। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह नेटवर्क की

मौजूदगी और स्थानीय स्वायत्त शासन के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें सामुदायिक रसोई संचालित करने का काम दिलाने में मदद की। बिहार, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश और ओडिशा के पांच राज्यों में चलाई जा रही 10,000 सामुदायिक रसोइयां इनमें से कुछ हैं। इन राज्यों के 75 अलग-अलग जिलों में फैली ये रसोइयां लगभग 70,000 जरूरतमंद व्यक्तियों को दिन में दो बार भोजन उपलब्ध करा रही हैं। अन्य राज्य भी इस तरह की पहल कर रहे हैं।

केरल एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस से संक्रमिल मामले सबसे ज्यादा हैं। यहां पर स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कुदुम्बस्वसहायता समूह की महिलाएं ऐसी जगहों पर सामुदायिक रसोई चला रही हैं जहाँ प्रवासी श्रमिक और गरीबी से त्रस्त परिवार हैं। भोजन में मुख्य रूप से घी चावल और चिकन करी दी जाती है। रसोई में तैयार खाने को स्वसहायता समूह, छोटे पैकेटों में बंद कर ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाते हैं। ये खाना उनलोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होता रहा है जो अपने घरों में क्वारंटीन में हैं और जिसकी वजह से उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

त्रिपुरा में सामुदायिक रसोई के ठेके राज्य सरकार की ओर से ऐसेस्वसहायता समूहों को दिए गए हैं जिनके पास खानपान व्यवसाय है या बड़ी मात्रा में खाना पकाने का पहले से कोई अनुभव है।

अरुणाचल प्रेदश में महिला स्वसहायता समूहों ने प्रशासन को नकद राशि का योगदान किया है और साथ ही कोविड की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को नाश्ता,खाना ,चाय और स्नैक्स उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को मुफ्त सिले मास्क, चावल और सब्जियाँ आदि भी दे रहे हैं।

ओडिशा में,6 लाख मिशन शक्ति स्वसहायता समूह की लगभग 70 लाख महिला सदस्य सामुदायिक रसोई द्वारा अनाज, किराने का सामान और पका हुआ भोजन जैसी बुनियादी चीजें मुहैया करा रही हैं। मिशन शक्ति के तहत लगभग 45,000 लोगों का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखंड सरकार ने मुख्य मंत्री दीदी रसोई के नाम से सामुदायिक रसोई शुरु की है। इसके जरिए गांवों में बेहद निर्धन परिवारों, दिव्यांगजनों और बच्चों तथा बेहद जरुरमंदों को खाना दिया जाता है। राज्य के 4185 ग्राम पंचायतों में ऐसी सामुदायिक रसोइयां चलाई जा रही हैं।

जम्मू कश्मीर में स्वसहायता समूह फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की जरुरतों को पूरा करने के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर में रहें सुरक्षित रहें के पालन के लिए यह भी आवश्यक है कि हर परिवार को उसके घर के दरवाजे पर या पास में सभी आवश्यक सामान और सेवाएं मिलती रहें। इसे ध्यान में रखते हुए ही देशभर में स्वसहायता समूहों ने विभिन्न तरह की पहल शुरु की है। उनकी ओर से यह काम आवश्यक सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है। ये स्वसहायता समूह अनाज ,पका खाना, ताजी सब्जियां और महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई के लिए आवश्यक वस्तुएं सीधे घरों तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन -एनआरएलएम आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य प्रकार के वाहनों का उपयोग विभिन्न राज्यों में इस कार्य के लिए किया जा रहा है।

मौजूदा चुनौतीपूर्ण हालात में वेजीटेबल्स ऑन व्हील्स और फ्लोटिंग सुपरमार्केट जैस प्रयोग दीदी स्वसहायता समूहों की ओर से एक बड़े समाधान के रूप में सामने आए हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, महिलाएं टेक होम राशन के साथ-साथ अंडे भी वितरित कर रही हैं।

दिल्ली-एनसीआर में दूसरे दिन भी भूकंप के झटके

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को भी भूकंप के मामूली झटके महसूस किये गये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पिछले 24 घंटों में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र के अनुसार, दोपहर लगभग डेढ़ बजे आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.7 मापी गई। दोपहर एक बजकर 26 मिनट पर आये इस भूकंप का केन्द्र जमीन से पांच किमी की गहराई में स्थित था।

उल्लेखनीय है कि रविवार को भी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 3.5 तीव्रता के मध्यम श्रेणी के भूकंप के झटके महसूस किये गये थे। कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन है ऐसे में भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखे गए थे। रविवार को

भूकंप के रिएक्टेर स्केल की तीव्रता 4 के आसपास बताई गई थी। हालांकि, 6 के ऊपर तीव्रता होती है तो वहीं ज्यादा खतरनाक भूकंप माना जाता है। एक तरफ जहां लोग करोना के लगातार आए नए केस के चलते अपने घरों में हैं तो वहीं भूकंप के चलते लोग बाहर निकलते दिखे हैं। ऐसे में अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बहुत जल्द भूकंप का केन्द्र बताया जाएगा। भूकंप के झटके जब महसूस हो तो कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे इस दौरान लिफ्ट का प्रयोग न करें, अगर खाली मैदान मिले तो वहां पर जाएं। लेकिन, कोरोना संक्रमण के चलते इस समय अपने चेहरों को ढ़ककर रखे, खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसका जरूर पालन करें।

भारत-अमेरिका के बीच वर्चुअल नेटवर्क बनाने की पहल

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (आईयूएसएसटीएफ)ने कोविड-19 की चुनौतियों से निबटने के लिए एक ऐसा वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैंजिनके माध्यम से दोनों देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने देशों में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे और वित्तपोषण सुविधा की मदद से कोविड-19 से संबधित अनुसंधान के लिए मिलकर काम कर सकेंगे।ये प्रस्ताव ऐसे होने चाहिए जो कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों से निबटने के लिए किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों में भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी के

लाभों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकें।

कोविड-19 जैसी वैश्विक चुनौतियां ऐसे वैश्विक सहयोग और साझेदारी की मांग करती हैं, जिनमें सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरोंऔर उद्यमियों को एक साथ लाया जा सके ताकि न केवल मौजूदा महामारी के संकट का समाधान तलाशा जा सके बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी निबटने के तरीके खोजे जा सकें। आईयूएसएसटीएफ अपने मूल उद्देश्यों के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग की इस पहल को बढ़ावा दे रहा है।

मार्च 2000 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित आईयूएसएसटीएफ दोनों देशों की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त द्विपक्षीय संगठन है, जो सरकारों, शिक्षाविदों और उद्योगों के बीच गहन संपर्क के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देता है।भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अमेरिका का विदेश विभाग इसकी नोडल एजेंसियां हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का कहना है कि कोविड-19के प्रकोप के समय में विज्ञान, वैश्विक स्तर पर प्रभावी संचार, आवश्यक-मान्यताओं, सहयोग, गति परिवर्तन और तकनीकी पहलुओं, पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक लाभतथा समस्या को हल करने के लिए एक सामान्य उत्साह जैसे तत्वों को सामने ला रहा है। इससे जो प्रभावी समाधान निकल कर आएंगे वे पूरे विश्व के लिए लाभप्रद हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वापसी संबंधी याचिकाओं को चार सप्ताह तक टाला

» विदेशों में फंसे भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने संबंधी सभी याचिकाओं को चार सप्ताह तक टाल दिया है। गौरतलब हो कि इस खतरनाक वायरस के प्रकोप के चलते विदेशों में रहने वाले बहुत से भारतीय वहीं फंसे हुए हैं।

इन लोगों की सरकार से गुजारिश है कि वह उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकालकर भारत वापस लाएं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कोर्ट से मांग की गई है कि वे सरकार को विदेशों

में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए निर्देश दें। वहीं, देश में लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीन दिन बाद रविवार को थोड़ी कमी आई। पिछले दिन से संक्रमित मरीजों की संख्या 800 के पार जा रही थी, लेकिन रविवार को यह संख्या 705 दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई और 705 नए मामले आए। इसी के साथ कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9152 हो गई है। इनमें 7987 सक्रिय हैं, 856 स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 308 लोगों की मौत हो गई है। आज नागालैंड में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। वहीं, महाराष्ट्र में 82, उत्तर प्रदेश के आगरा में 30, गुजरात में 22, मध्यप्रदेश के इंदौर में 22, कर्नाटक में 15, आंध्र प्रदेश में 12, राजस्थान में 43 और मुंबई के धारावी में चार नए मामले सामने आए हैं।

30 अप्रैल तक भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को मिल रही दूतावास की सेवाएं

नईदिल्ली (आरएनएस)। जनता के भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से यह सूचित किया जाता है कि कोविड 19 के प्रकोप के कारण यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वर्तमान में 30 अप्रैल 2020 तक भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 28 मार्च को निशुल्क आधार पर दूतावास की सेवाएं (या कांसुलर सर्विसिज) प्रदान की थीं। दुनिया के अनेक हिस्सों में कोविड-19 फैल जाने और उसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा संबंधी प्रतिबंधों की वजह से भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के नियमित वीज़ा, ई-वीज़ा या स्टे स्टेपुलेशनतथा ऐसे विदेशी नागरिक जिसके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है या 01.02.2020 (मध्यरात्रि) से 30.04.2020 (मध्यरात्रि) के दौरान समाप्त हो रही है, तो उसे विदेशी नागरिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, निशुल्क आधार पर 30 अप्रैल 2020 (मध्यरात्रि) तक बढ़ाया जाएगा।

कोरोना के बीच कर्मचारियों को वेतन मिलता रहेगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना के कहर के कारण देश और दुनिया मानो थम से गए हैं। इस बीच भारत और राज्य सरकारों के लिए तैयार कैश मैनेजमेंट प्लान के तहत विभिन्न विभागों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की बाधा न हो। हालांकि, वित्तीय जरूरतों और राजस्व की कमी के चलते एरियर 30 जून तक अटक सकता है।

कई राज्य सरकारों ने केंद्र से वित्तीय मदद की मांग की है। राज्यों का कहना है कि वे सभी जरूरी खर्च की अनुमति दे रहे हैं लेकिन उनके राजस्व का बड़ा हिस्सा कोविड-19 के खिलाफ तैयारियों पर खर्च हो रहा है। आय के स्रोत घटे हैं और इनकी उचित भरपाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल केंद्रीय योजनाओं में आवंटित धनराशि को भी कुछ राज्यों ने बिना अनुमोदन खर्च न करने के आदेश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक कोरोना से जंग में शामिल योद्धाओं को समय पर वेतन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है। देश में कोरोना पीड़ितों की तादाद आठ हजार के पार पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार देर शाम जारी आंकड़ों के अनुसार, मरीजों की संख्या 8447 जबकि मृतकों की संख्या 273 तक पहुंच गई है।

नौसेना क्वारंटाइन शिविर से घर वापस लौटे 44 विस्थापित

मुंबई (आरएनएस)। मैटेरियल ऑर्गनाइजेशन, घाटकोपर, मुंबई स्थित भारतीय नौसेना क्वारंटाइन इकाई ने ईरान से लाए गए 44 विस्थापितों (24 महिलाओं सहित) के क्वारंटाइन (एकांत) का काम शांतिपूर्वक और सफलता से पूरा कर लिया है। कुल मिलाकर, 44 लोगों ने इस इकाई में 13 मार्च, 2020 से अभी तक 30 दिन बिताए। इसके साथ ही 28 मार्च को कराई गई कोविड 19 जांच में इनमें से हरेक का परीक्षण निगेटिव रहा।

नौसेना के स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक समर्पित दल लगातार विस्थापितों के स्वास्थ्य की निगरानी में लगा रहा। उनको इकाई की स्वच्छता, उनके आराम और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सफाईकर्मियों और अन्य कर्मचारियों की तरफ से पूरा सहयोग हासिल हुआ।

उपलब्ध कराया गया भोजन सख्त निगरानी में तैयार किया गया और किसी प्रकार की विशेष जरूरतों के आधार पर उसमें बदलाव किया गया। विस्थापितों को व्यस्त रखने और क्वारंटाइन इकाई को आरामदायक बनाए रखने के लिए हर सुविधा भी दी गई। इनमें एक पुस्तकालय, टीवी का कमरा, इंडोर गेम, एक छोटा जिम और सीमित क्रिकेट गियर शामिल हैं।

राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू लॉकडाउन के चलते स्टोर्स की सीमित उपलब्धता से पैदा हुई अतिरिक्त चुनौतियों से उबरने में नवाचार और संकल्प के माध्यम से खासी मदद मिली। इसके अलावा विस्थापितों के रहने का समय बढ़ गया था, क्योंकि उनके पास श्रीनगर और लद्दाख स्थित अपने घर तक जाने का कोई साधन नहीं था। इसके बाद भारतीय वायुसेना के विमानों के माध्यम से उन्हें भेजने की व्यवस्था की गई थी और12 अप्रैल, 2020 को एक सी-130 विमान के माध्यम से इन लोगों को श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। वापसी की यात्रा के लिए हर विस्थापित को एनडब्ल्यूडब्ल्यूए घाटकोपर के सौजन्य से डिब्बाबंद खाना, अल्पाहार और दो हाथ से बने मास्क उपलब्ध कराए गए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विकसित किये दोहरी परत वाले खादी मास्क

नई दिल्ली (आरएनएस)। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने सफलतापूर्वक एक दोहरी परत वाले खादी मास्क का विकास कर लिया है और उसे बड़ी मात्रा में इन मास्क की आपूर्ति करने के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। अपनी इस सफलता के साथ, केवीआईसी ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार को 7.5 लाख खादी मास्क की आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त किया है जिसमें 5 लाख मास्क जम्मू जिले को, एक लाख चालीस हजार पुलवामा जिले को, एक लाख उधमपुर जिले और 10,000 कुपवाड़ा जिले को दिए जाएंगे। इन मास्क की आपूर्ति 20 अप्रैल तक इन जिलों के विकास आयुक्तों को की जाएगी। कॉटन के दोबारा इस्तेमाल में लाए जा सकने वाले ये मास्क 7 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े होंगे, इनमें तीन सलवटें होंगी और बांधने के लिए कोनों में चार पट्टियां होंगी।

केवीआईसी अध्यक्ष वी. के. सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी इन मास्क के निर्माण के लिए दो परत वाले खादी कपड़े का खास तौर पर उपयोग कर रहा है क्योंकि ये अंदर की नमी को 70 फीसदी बनाए रखने में मदद करता है, और हवा को गुजरने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है, जिस

कारण से ये सबसे अच्छा, आसानी से उपलब्ध, जेब में आ सकने वाला वैकल्पिक फेस मास्क है। सक्सेना ने कहा कि ये मास्क ज्यादा विशेष इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े से बने हैं जो कि सांस लेने योग्य होते हैं, आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं और धोने योग्य व बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वर्तमान में जम्मू के पास नगरोटा में खादी सिलाई केंद्र को एक मास्क सिलाई केंद्र में बदल दिया गया है, जो प्रति दिन 10,000 मास्क का उत्पादन कर रहा है, वहीं शेष ऑर्डर श्रीनगर में या आसपास के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और खादी संस्थानों में बांटे जा रहे हैं। इस बीच देश भर में स्थानीय प्रशासन का समर्थन करने के लिए केवीआईसी अध्यक्ष द्वारा सभी खादी संस्थानों को अपील जारी की गई है कि वे कम से कम 500 मास्क अपने संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों को उपयोग और आगे वितरण के लिए मुफ्त में दें। केवीआईसी में 2400 सक्रिय खादी संस्थान हैं और इस कदम से देश भर में 12 लाख मास्क प्रदान किए जाएंगे। अपील के बाद कई खादी संस्थानों ने जिला कलेक्टरों को 500 मास्क प्रदान करने शुरू कर दिए हैं। श्री सक्सेना ने कहा, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए फेस मास्क सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं।